Q नैतिकता समाज में क्या भूमिका निभाती है ? उदाहरण द्वारा समझाइए

What is the role of ethics in society? Explain with example

जिन मूल्यों से निर्देशित होकर मनुष्य अपने व्यवहार को शुभ-अशुभ,उचित-अनुचित,पाप-पुण्य की कसौटी पर जांचने लगता है, नैतिकता कहलाता है।

मनुष्य एक सामाजिक प्राणी होने के साथ-साथ समाज की इकाई भी है अतः दोनो एक दूसरे के पूरक हैं। समाजिक मूल्य मनुष्य के व्यवहार को निर्देशित करता है और मनुष्य अपने व्यवहारों से सामाजिक मूल्यों का निर्माण करता है। विकास की धारा में निरन्तर आगे बढ़ते हुए आज का मनुष्य अपने सामाजिक रूप को पीछे छोड़ते हुए आर्थिक एवम् तकनीकी रूप को ग्रहण कर कर चुका है। इस क्रम में नैतिकता का हुआ भी हुआ। युवाओं में सामाजिक दायित्व की भावना का अभाव, महिलाओ एवम् बच्चों के प्रति बढ़ता दुर्व्यवहार, भ्रष्टाचार का बहुआयामी रूप, कमजोर वर्गों के प्रति असंवेदनशीलता की भावना आदि के रूप में इसको देखा जा सकता है। ऐसे में सामाजिक मूल्यों यथा- परस्पर सहयोग की भावना का विकास,समानता,सहअस्तित्व, सहानभूति एवम् समानभुति आदि का विकास करने में सामाजिक नैतिकता की प्रासंगिकता बढ़ जाती है।

नैतिकता समाज की जड़ता को समाप्त करता है।महिलाओं में शिक्षा का बढ़ता स्तर समाज में नैतिकता के विकास का ही परिणाम है। धीरे-धीरे ही सही परन्तु इससे महिलाओं के प्रति समाजिक सोच में बदलाव आ रहा है तभी तो समाज की संकीर्ण मानसिकता को धत्ता बता कर सानिया मिर्ज़ा,साक्षी मलिक, पी वी सिंधु जैसी लड़कियाँ आज देश का प्रतिनिधित्व कर रही है। गांवो में परस्पर सहभागिता का प्रतीक बन चुका स्वयं सहायता समूह का अस्तित्व भी समाज में बढ़ती नैतिकता पर ही टिका हुआ है। परन्तु कुछ मामलों में नैतिकता समाज को नकारात्मक रूप से भी प्रभावित करता है। जिसको बाल-विवाह, दहेज-प्रथा, बालिका शिशु हत्या, ऑनर किलिंग आदि के रूप में देखा जा सकता है। इस तरह की सामाजिक रूढ़िवादिता समाज में नैतिक द्वन्द्व को जन्म देता है और समाजिक प्रभाव के कारण लोग इस अनैतिकता को भी सामाजिक नैतिकता का हिस्सा मान लेते हैं।

वर्तमान में समाज संक्रमण की दौर से गुजर रहा है। जहां पारम्परिक मूल्य एवम् पाश्चात्य संस्कृति के मूल्य आपस में द्वंदात्मक स्थिति में और ये द्वन्द्व ही अनेक विकृतियों के रूप में उभर कर सामने आने लगता है। ऐसे में समाज के प्रति सकारात्मक नैतिकता की भुमिका बढ़ जाती है। जिसको मनुष्य अंतरात्मा की आवाज एवम् मनसा-वाचा-कर्मणा के वशीभूत होकर इसको प्रायोगिक रूप दे सकता है।

भारत तेजी से उभरती हुई अर्थव्यवस्था में सुमार किया जाता है। ऐसे में इस निरन्तरता को बनाए रखने के लिए स्वस्थ कार्यबल की आपूर्ति अनिवार्य है। सरकार के द्वारा इसके लिए प्रयास

भी किया जा रहा है परन्तु हाल में जारी वैश्विक भूख सूचकांक में 118 देशो की सूची में भारत को 97 वाँ स्थान पर रखा गया जोकि इसकी नकारात्मक छवि प्रस्तुत करती है।

बच्चे देश के भविष्य होते हैं। बच्चे के स्वास्थ्य का सीधा सम्बन्ध उसकी माँ से होता है अतः स्वस्थ एवम् सुपोषित बच्चे के जन्म के लिए माँ का स्वस्थ होना आवश्यक है। देश में बढ़ते कुपोषण की समस्या एवम् इसकी गम्भीरता को देखते हुए सरकार के द्वारा जननी सुरक्षा योजना, एकीकृत बाल विकास योजना, मध्यान भोजन योजना जैसी कई कल्याणकारी योजनाओं को भी लागू किया है। इसी के अंतर्गत खाद्य सुरक्षा अधिनियम को क्रांतिकारी पहल के रूप मे देखा जा सकता है। परन्तु हाल की कई रिपोर्टो ने इसकी सार्थकता पर प्रश्न चिह्न लगा दिया है। इसको सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक कारकों के परिप्रेक्ष्य में समाझा जा सकता है---- पितृसत्तात्मक समाज होने के कारण आरम्भ से ही महिलाओं को दोयम दर्जे में रखा गया है। शिक्षा से लेकर भोजन तक में उनके साथ भेदभाव किया जाता है। अक्सर महिलाएं बाद में बचा हुआ भोजन करती है जो उनके लिए अपर्याप्त होता है और कभी कभी ऐसे भोजन की गुणवत्ता भी खराब होती है। गरीबी अभी भी विकासशील भारत के लिए अभिशाप बना हुआ है। निम्न क्रय शक्ति होने के कारण गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोग के भोजन में उपयुक्त पोषकता की कमी पाई जाती है। दोषपूर्ण शिक्षा प्रणाली के कारण जागरूकता का अभाव एवम् जागरूकता के बाद भी आर्थिक स्रोतों तक पहुंच ना होने के कारण महिलाये बाध्य हो जाती है। भारत हमेशा से ही पॉलिसी पैरालाइसिस का शिकार रहा है। योजनाओं तो लागू कर दी जाती है लेकिन उसके क्रियान्वयन एवम् मोनिटरिंग के लिए पर्याप्त कदम नहीं उठाये जाते है जिससे ये योजनाये प्रभावशाली होने के बावजूद अपने उद्देश्य में असफल हो जाती है।

कुपोषण एक बहुआयामी समस्या है अतः इसके लिए ठोस कदम के साथ साथ इसके क्रियान्वयन की राजनीतिक इच्छा शक्ति भी दिखानी होगी।जेंडर बजटिंग के माध्यम से महिलाओ को विशेष लाभ दिया जा सकता है।मोनिटरिंग का तन्त्र निचले स्तर तक प्रभावी हो तभी कुपोषण को प्रारम्भिक अवस्था में ही ट्रैक किया जा सकता है। संयुक्त राष्ट्र के मुताबिक दुनिया में एक तिहाई भोजन बर्बाद हो जाता है। इसके लिए कई संरचनात्मक कारक भी जिम्मेदार है। भारत भी इस समस्या से जूझ रहा है अतः खाद्य पदार्थों के परिवहन एवम् प्रसंस्करण के लिए आवश्यक कदम उठाने की आवश्यकता है जिससे अधिकतम भोजन को अधिकतम लोगो को सुलभ हो सके। बिभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से अशिक्षित जनता में स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता लानी चाहिए था शिक्षा का ज्यादा से ज्यादा प्रसार कर भविष्य की पीढ़ी को कुपोषण के दंश से बचाया ज सकता है।